इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 554]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2017—आश्विन 21, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्र. एफ ए 3-70-2017-1-पांच (127).—

राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- वे उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।
- 2. मध्यप्रदेश माल और सेवाकर नियम, 2017 में,-
  - (i) नियम 3 में, उपनियम (3क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3क) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण अनुदत किया गया है या जिसे नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत किया गया है, धारा 10 के अधीन उस मास के, जिसमें उसने सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से 31 मार्च, 2018 को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संसूचना फाइल करता है, के तुरंत उत्तरवर्ती मास की पहली तारीख से कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में उस दिन, जिसको ऐसा व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का संदाय करना आरंभ करता है, से नब्बे दिन की अविध के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा :

परंतु उक्त व्यक्तियों को प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुजात नहीं किया जाएगा।";

- (ii) नियम 46 के पश्चात् निम्निलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-"46क. पूर्ति का बीजक-सह-बिल- नियम 46 या नियम 49 या नियम 54 में अंतर्विष्ट
  किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी गैररिजस्ट्रीकृत व्यक्ति
  को कराधेय मालों के साथ छूट प्राप्त मालों या सेवाओं की पूर्ति करता है, तो वह ऐसी
  पूर्तियों के लिए, एकल "पूर्ति का बीजक-सह-बिल" जारी कर सकेगा।";
  - (iii) नियम 54 के उपनियम (2) में,-
    - (क) "कर बीजक" शब्दों के स्थान पर, "समेकित कर बीजक" शब्द रखे जाएंगे ;
    - (ख) "चाहे किसी भी नाम से जात हो" शब्दों के पश्चात, "मास के अंत में मास के दौरान सेवाओं की पूर्ति के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- (iv) नियम 62 के उपनियम (1) में निम्निलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
  "परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उस मास की पहली तारीख से, जो तिमाही का पहला

  मास नहीं है, धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, प्ररूप

  जीएसटीआर-4 में तिमाही की उस अवधि के लिए, जिसके लिए उसने धारा 10 के अधीन

  कर का संदाय किया है विवरणी प्रस्तुत करेगा और वह धारा 10 के अधीन कर संदाय

  का विकल्प लेने से पूर्व तिमाही की अवधि के लिए उसे यथा लागू विवरणियां प्रस्तुत

  करेगा।";
  - (v) प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में "देखें नियम 3(2)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "देखें नियम 3(3) और 3(3क)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
  - (vi) प्ररूप जीएसटीआर-1 में सारणी 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"6 शून्य दर पूर्तियां और माने गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			परिवहन बिल/निर्यात बिल		एकीकृत कर			उपकर
	सं0	तारीख	मूल्य	सं0	तारीख	दर	कराधेय मूल्य	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6क. निर्यात			I		1		·		
6ख. एसईजेड इंकाइयों या एसईजेड विकासकर्ता को की गई पूर्तियां									

6ग. माना गया निर्यात					
					",

(vii) प्ररूप जीएसटीआर-1क में सारणी 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--"4 एसईजेड को की गई शून्य दर पूर्तियां और माने गए निर्यात

1	तकर्ता का सटीआईएन	बी	जक के इ	यौरे		एकीकृत कर		उपकर
		सं0	तारीख	मूल्य	दर	कराधेय मूल्य	कर रकम	
	1	· 2	3	4	5	6	. 7	8
	एसईजेड इव		एसईजेड 1	विकासकर	र्ताको की व	गई पूर्तियां		
4ख.	माना गया	नियात						
							:	";

(viii) प्ररूप जीएसटी आर-4 में, अनुदेश सं0 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"10. जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017 और अक्तूबर, 2017 से दिसंबर, 2017 कर अविध के लिए सारणी 4 की क्रम सं0 4क प्रस्तृत नहीं की जाएगी"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण परमार, उपसचिव.

## भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्र. एफ ए 3-70-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-70-2017-1-पांच (127), दिनांक 13 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण परमार, उपसचिव.

#### Bhopal, the 13th October 2017

No. F A 3-70-2017-1-V(127).—

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), the State Government, hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- 1. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, -
  - (i) in rule 3, for sub-rule (3A), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
    - "(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), a person who has been granted registration on a provisional basis under rule 24 or who has been granted certificate of registration under sub-rule (1) of rule 10 may opt to pay tax under section 10 with effect from the first day of the month immediately succeeding the month in which he files an intimation in **FORM GST CMP-02**, on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, on or before the 31<sup>st</sup> day of March, 2018, and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 within a period of ninety days from the day on which such person commences to pay tax under section 10:

Provided that the said persons shall not be allowed to furnish the declaration in **FORM GST TRAN-1** after the statement in **FORM GST ITC-03** has been furnsihed.";

- (ii) after rule 46, the following rule shall be inserted, namely:-
  - "46A. Invoice-cum-bill of supply.- Notwithstanding anything contained in rule 46 or rule 49 or rule 54, where a registered person is supplying taxable as well as exempted goods or services or both to an unregistered person, he may issue a single "invoice-cum-bill of supply" for all such supplies.";
- (iii) in rule 54, in sub-rule (2),
  - (a) for the words "tax invoice" the words "consolidated tax invoice" shall be substituted;
  - (b) after the words "by whatever name called", the words "for the supply of services made during a month at the end of the month" shall be inserted;
- (iv) in rule 62, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the registered person who opts to pay tax under section 10 with effect from the first day of a month which is not the first month of a quarter shall furnish the return in **FORM GSTR-4** for that period of the quarter for which he has paid tax under section 10 and shall furnish the returns as applicable to him for the period of the quarter prior to opting to pay tax under section 10.";

(v) in FORM GST CMP-02, for the words, figures and brackets "See rule 3(2)", the words, figures, brackets and letter "See rule 3(3) and 3(3A)" shall be substituted;

(vi) in FORM GSTR-1, for Table 6, the following shall be substituted, namely:-

#### "6. Zero rated supplies and Deemed Exports

GSTIN of recipient	Invoice details				bill/Bill xport	Integrated Tax			Cess
•	No.	Date	Value	No.	Date	Rate	Taxable value	Amt.	•
1	2	3	4	. 5	6	7	8	9	10
6A. Exports				•					
					•				-
6B. Supplies n Developer	nade to	SEZ u	nit or SE	Z		, <del>,</del>			
6C. Deemed e	xports	<u> </u>							
									27,

(vii) in FORM GSTR-1A, for Table 4, the following shall be substituted, namely:-

### "4. Zero rated supplies made to SEZ and deemed exports

GSTIN of recipient	Invoice details				Cess		
•	No.	Date	Value	Rate	Taxable value	Tax amount	
1	2	3	4	5	6	7	8
4A. Supplies made to S	SEZ un	it or SE	Z Develo	per			
		,					
•							
4B. Deemed exports		<u> </u>					
			1	<u> </u>			
. •							. ***

(viii) in **FORM GSTR-4**, after instruction no.9, the following shall be inserted, namely:"10. For the tax period July, 2017 to December, 2017, serial 4A of Table 4 shall not be furnished."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ARUN PARMAR, Dy. Secy.